

## मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रव्यापी स्कूली बच्चों के पोषण संबंधी दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। [१] यह कार्यक्रम सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय, शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक शिक्षा केंद्र, मदरसा और मकतब में सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित, और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के लिए काम के दिनों में मुफ्त लंच की आपूर्ति करता है। श्रम मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। [२] 1,265,000 से अधिक स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों में 120,000,000 बच्चों की सेवा करना, यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा है।

## केंद्र सरकार द्वारा पहल

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल में मिड-डे मील योजना शुरू की

भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा (एनपी-एनएसपीई) को राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम शुरू किया। [३] योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूल के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा की प्रभावशीलता में सुधार करना है। प्रारंभ में, यह योजना देश के 2,408 खंडों में लागू की गई थी, जो सरकारी, सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय संचालित स्कूलों में से एक के माध्यम से कक्षा एक में छात्रों को भोजन प्रदान करती हैं। 1997-98 तक यह योजना देश भर में लागू हो गई थी।

इस कार्यक्रम के तहत, कक्षा एक से पांच में नामांकित सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के साथ एक पकाया हुआ मिड डे मील प्रदान किया जाता है। अक्टूबर 2007 में, इस योजना में 3,479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में छह से आठ तक के उच्च प्राथमिक वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया, [13] और इसका नाम स्कूलों में मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम से बदल दिया गया। [14] हालाँकि पका हुआ भोजन प्रदान किया जाना था, अधिकांश राज्यों (छात्रों को पहले से ही पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के अलावा) ने छात्रों को "सूखा राशन" प्रदान करने के लिए चुना। "सूखा राशन" 80% उपस्थिति वाले बच्चों को बिना पकाए 3 किलो गेहूं या चावल के प्रावधान को संदर्भित करता है।

## सुप्रीम कोर्ट का आदेश

अप्रैल 2001 में, पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) ने जनहित याचिका (सिविल) नंबर 196/2001, पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य [15] शुरू की - जिसे "अधिकार" के रूप में जाना जाता है। भोजन "मामला। पीयूसीएल ने भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद 21 - "जीवन के अधिकार" का तर्क दिया, जब लेख 39 (ए) और 47 के साथ एक साथ पढ़ा जाता है, एक मौलिक भोजन का अधिकार बनाता है जो अनुच्छेद 32 के अनुसार प्रदान किए गए संवैधानिक उपाय के आधार पर लागू होता है। संविधान का। पीयूसीएल ने तर्क दिया कि भारतीय खाद्य निगम के साथ अतिरिक्त खाद्य भंडार भूखे नागरिकों को खिलाया जाना चाहिए। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना शामिल था। यह

योजना 28 नवंबर, 2001 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ लागू हुई, [16] जिसमें सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों को पका हुआ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है। [१ with]

**Website <http://mdm.nic.in/>**